BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस

"भारत की डेयरी शक्ति और किसान समृद्धि का उत्सव"

25 नवंबर, 2026

भारत की पोषण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में दुग्ध

देश के पोषण परिदृश्य में दुग्ध का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह उच्च गुणवत्ता वाले पशु प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्व, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटैशियम प्रदान करता है, जो आसानी से अवशोषित होने वाले रूप में होते हैं। अक्सर दूध को लगभग पूर्ण भोजन माना जाता है, सभी आयु वर्गों में विकास, हड्डियों के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का प्रदान करता है।

भारत लगातार विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बना हुआ है, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन का लगभग एक-चौथाई योगदान देता है। वर्ष 2014-15 और वर्ष 2024-25 के बीच, उत्पादन 5.41 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा, जो 247.87 मिलियन टन तक पहुंच गया। इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण ग्रामीण आयाम भी है। डेयरी 8.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को आजीविका प्रदान करता है, जिसमें महिलाएं दुग्ध उत्पादन और संग्रह में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। भारत के डेयरी उत्पादन कार्यबल का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा महिलाएं हैं, जो इस क्षेत्र की वृद्धि में उनके योगदान और समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को उजागर करता है।

प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस डॉ. वर्गीस कुरियन की जयंती का स्मरण करता है, जो देश की श्वेत क्रांति के जनक थे। यह दिन भारत के डेयरी सहकारी आंदोलन में उनके परिवर्तनकारी योगदान को मान्यता देता है। यह उन लाखों डेयरी किसानों को सम्मानित करता है जिनके प्रयास देश के दुग्ध उत्पादन में नेतृत्व को बनाए रखते हैं।

भारत के डेयरी क्षेत्र में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई

भारत ने उत्पादन और उत्पादकता में निरंतर वृद्धि के सहयोग से विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनने की स्थिति बनाए रखी है।

- दुग्ध उत्पादन 69.41 प्रतिशत बढ़ा, जो वर्ष 2014-15 में 146.31 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में **247.87 मिलियन टन** हो गया।

- प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश (**15.66 प्रतिशत**), राजस्थान (14.82 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (9.12 प्रतिशत), गुजरात (7.78 प्रतिशत), और महाराष्ट्र (6.71 प्रतिशत) थे। ये पांच राज्य देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 54.09 प्रतिशत थे।
- प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता 52.03 प्रतिशत बढ़ी, जो वर्ष 2014-15 में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 319 ग्राम थी, और वर्ष 2024-25 में **485 ग्राम** हो गई।
- औसत गौ दुग्ध उत्पादकता 2014-15 में प्रति पशु प्रति वर्ष 1,640 कि.ग्रा. से बढ़कर वर्ष 2024-25 में **2,800 कि.ग्रा.** प्रति पशु प्रति वर्ष हो गई, जो **69 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज करती है।

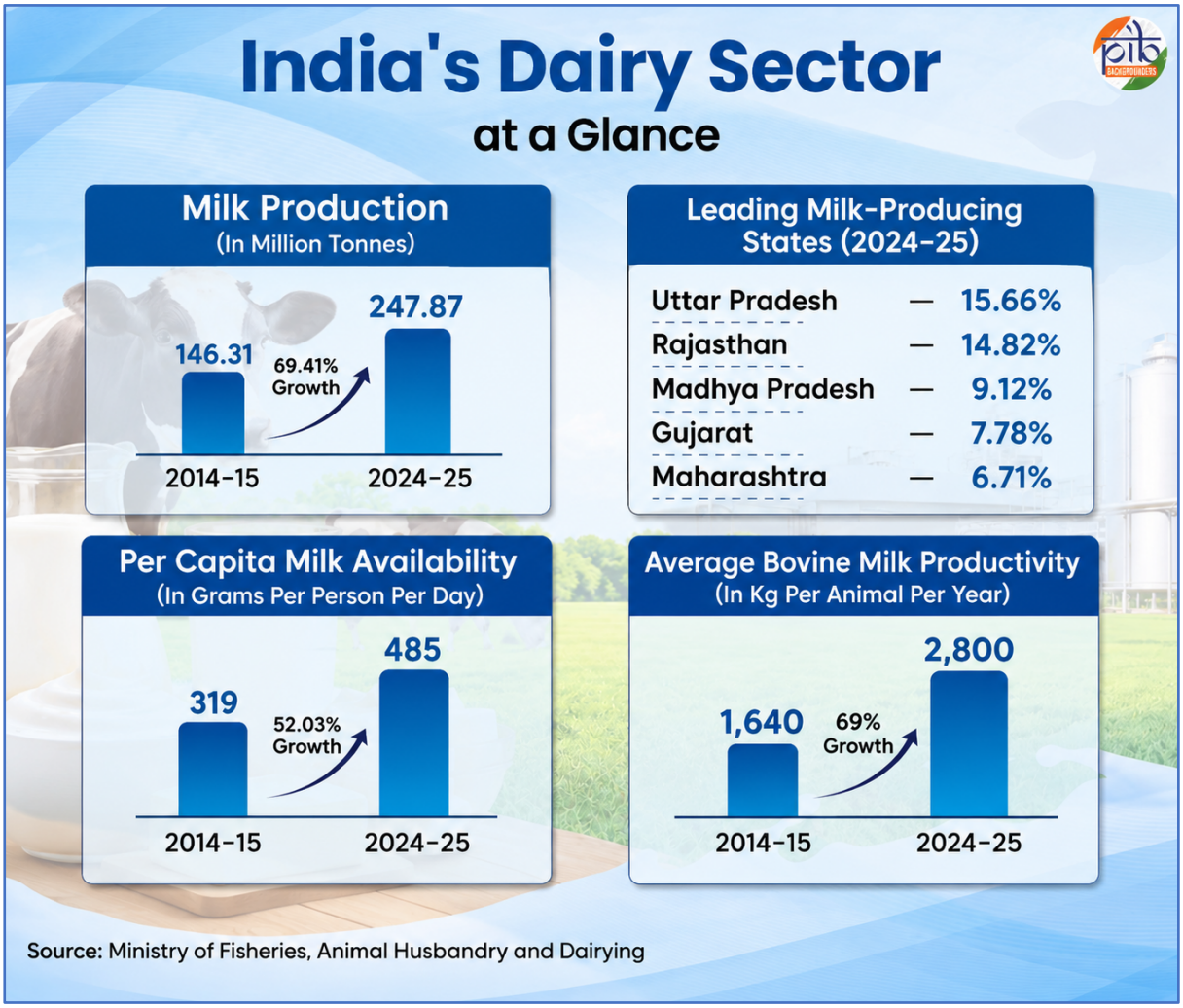

भारत की दुग्ध अर्थव्यवस्था के पीछे सहकारी शक्ति

भारत का डेयरी सहकारी आंदोलन दुग्ध उत्पादकों के लिए एक संगठित मंच प्रदान करता है। यह गांव स्तर की समितियों को जिला दुग्ध संघों और राज्य संघों से जोड़ता है। ये संस्थान दुग्ध खरीद, प्रसंस्करण, विपणन और डेयरी सेवाओं तक पहुंच का सहयोग करते हैं।

भारत के डेयरी क्षेत्र की ऐतिहासिक यात्रा को जानने के लिए: यहाँ क्लिक करें

देश का डेयरी सहकारी नेटवर्क शामिल है:

- **22** दुग्ध संघ
- **241** जिला सहकारी दुग्ध संघ
- **28** मार्केटिंग डेयरी
- **25** दुग्ध उत्पादक संगठन
- लगभग 2.45 लाख गांवों और 1.65 करोड़ डेयरी किसानों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया

यह नेटवर्क ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों और संगठित डेयरी बाजारों के बीच एक संस्थागत संबंध प्रदान करता है। यह सामूहिक विपणन और बेहतर संगठित दुग्ध खरीद प्रणालियों तक पहुंच का भी समर्थन करता है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के डेयरी सर्विसेज

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड-एनडीडीबी ने भारत में किसान-स्वामित्व वाली डेयरी संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली, गैर-लाभकारी सहायक कंपनी, **एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (एनडीडीबी-डीएस),** दुग्ध उत्पादक संगठनों (**एमपीओ**) के निगमन और संचालन को सुगम बनाती है।

एमपीओ किसान-स्वामित्व वाली उत्पादक कंपनियां होती हैं जो दुग्ध उत्पादकों को पेशेवर रूप से प्रबंधित संस्थानों में संगठित करती हैं। वे सामूहिक दुग्ध खरीद को सुविधाजनक बनाती हैं, बाजार संबंधों को मजबूत करती हैं, और किसानों को पारदर्शी मूल्य निर्धारण और सीधे बैंक भुगतान तक पहुंच प्रदान करती हैं।

31 अक्टूबर 2026 तक,

- एनडीडीबी-डीएस ने सफलतापूर्वक 25 एमपीओ स्थापित किए हैं।
- इन 25 एमपीओ में से 18 में सभी महिला सदस्य हैं, और महिलाएं अपने-अपने बोर्ड में निर्माता निदेशक के रूप में कार्य करती हैं।
- ये संगठन 12 राज्यों के **175 जिलों** में **13 लाख** से अधिक दुग्ध उत्पादकों को कवर करते हैं।
- इन संगठनों में उत्पादकों में लगभग 78 प्रतिशत महिलाएं हैं।
- एमपीओ प्रतिदिन लगभग 70 लाख लीटर दुग्ध खरीदते हैं।

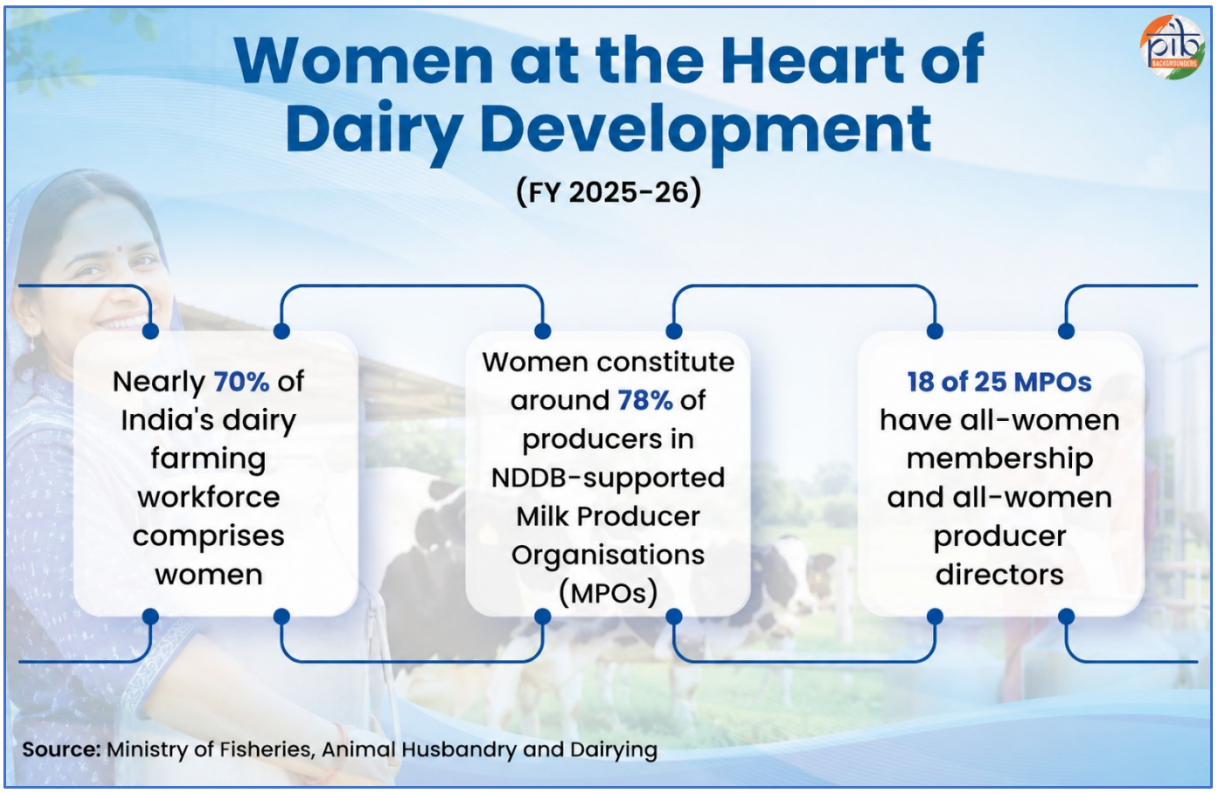

डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध की खरीद और बिक्री

डेयरी सहकारी समितियाँ किसानों के लिए एक संगठित बाजार प्रदान करती हैं और दुग्ध की नियमित खरीद सुनिश्चित करने में मदद करती हैं। खरीद मूल्य सहकारी समितियों और अन्य डेयरी द्वारा उत्पादन लागत और बाजार की स्थितियों के आधार पर तय किए जाते हैं। कई डेयरी सहकारी समितियां स्वचालित दुग्ध संग्रह और भुगतान प्रणालियों का उपयोग करती हैं। भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किए जाते हैं।

31 अक्टूबर 2026 तक**,** डेयरी सहकारी समितियों ने दर्ज किया:

- 690.90 लाख किलोग्राम प्रति दिन दुग्ध की खरीद।
- 462.95 लाख लीटर प्रति दिन तरल दुग्ध की बिक्री।

डेयरी सहकारी समितियों के लिए एक नई गति

श्वेत क्रांति 2.0, सहकारी नेतृत्व वाली पहल जिसे 25 दिसंबर 2024 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया (एसओपी 19 सितंबर, 2024 को शुरू किया गया), का उद्देश्य असम्मिलित गांवों और पंचायतों में डेयरी सहकारी कवरेज का विस्तार करना है। यह अगले पांच वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध की खरीद को **50 प्रतिशत** बढ़ाने का लक्ष्य रखता है । यह पहल सहकारी नेटवर्क को मजबूत करने, बाजार तक पहुंच सुधारने, रोजगार सृजन और महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियां राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के अंतर्गत वित्तपोषित हैं।

वर्ष 2028-29 तक, इस पहल का लक्ष्य असम्मिलित गांवों और पंचायतों में 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करना और 46,422 मौजूदा डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत करना है।

31 अक्टूबर 2026 तक श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत प्रगति,

- **24,097** नई डेयरी सहकारी समितियाँ बनाई गईं।
- **31,394** मौजूदा डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत किया गया।

<u>डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और चक्रीयता</u>

1. श्वेत क्रांति 2.0 डेयरी मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और चक्रीयता को बढ़ावा देता है। यह जलवायु-स्मार्ट प्रथाओं, कुशल संसाधन उपयोग और नवीकरणीय, कम उत्सर्जन समाधानों को प्रोत्साहित करता है। यह पहल '**कूड़े से सोना**' (मवेशी गोबर और कृषि अवशेषों को बायोगैस, जैविक खाद, और मूल्य-वर्धित जैव-उर्वरकों में बदलना) की दृष्टि को दो बहु-राज्य सहकारी समितियों के माध्यम से आगे बढ़ाती है:

- **कॉपरेटिव इनपुट और सर्विस डिलीवरी मल्टी-स्टेट लिमिटेड:** इसका उद्देश्य गुणवत्ता इनपुट और सेवाएं प्रदान करना है, जिसमें पशु चारा, रोग नियंत्रण, और कृत्रिम गर्भाधान शामिल हैं।
- **गोमय सहकारी समिति मल्टी-स्टेट लिमिटेड:** यह गोबर के वैज्ञानिक प्रबंधन और उपयोग पर केंद्रित है।

1. **गोबर्धन,** राष्ट्रीय सर्कुलर जैव ऊर्जा योजना, जो 01 अक्टूबर, 2026 को शुरू की गई**,** भारत की जैविक संपदा को स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आर्थिक विकास में बदलने का लक्ष्य रखती है। **23,731** करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष **2035-36** तक लागू की जाएगी**।**

यह सुनिश्चित ऑफटेक, स्थिर मूल्य निर्धारण, पूंजी सहायता, पाइपलाइन कनेक्टिविटी और क्रेडिट समर्थन के माध्यम से डोमेस्टिक कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाने का प्रयास करता है। यह ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, निजी निवेश को सक्रिय करेगा और सर्कुलर बायोइकोनॉमिक को बढ़ावा देगा।

गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबर्धन) पहल मूल रूप से वर्ष 2018 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत शुरू की गई थी। यह जैविक कचरे, जिसमें मवेशी के गोबर और कृषि अवशेष शामिल हैं, को बायोगैस और बायो-स्लरी में परिवर्तित करने को बढ़ावा देती है, जिससे गांव की सफाई, कचरा प्रबंधन और ग्रामीण आजीविका में सहयोग मिलता है।

ये पहलें संसाधन चक्रीयता को मजबूत करती हैं और ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करती हैं।

मजबूत डेयरी इकोसिस्टम का निर्माण

भारत का डेयरी क्षेत्र मजबूत अवसंरचना, वैज्ञानिक प्रजनन, गुणवत्तापूर्ण चारा और सुलभ पशु चिकित्सा देखभाल पर निर्भर करता है। सरकारी पहल इन क्षेत्रों को सुदृढ़ करती हैं, पशुपालन उत्पादकता बढ़ाती हैं, पशु स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं और डेयरी किसानों को लाभ देती हैं।

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के माध्यम से डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करना

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) का उद्देश्य देश भर में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना और डेयरी अवसंरचना को मजबूत करना है। यह दुग्ध खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन और दुग्ध गुणवत्ता अवसंरचना का समर्थन करता है।

यह कार्यक्रम डेयरी क्षेत्र के संतुलित विकास को दो घटकों के माध्यम से बढ़ावा देता है:

घटक क: दुग्ध खरीद और गुणवत्ता अवसंरचना को सुदृढ़ करना

यह संगठित दुग्ध खरीद नेटवर्क का विस्तार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुग्ध प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह गांव स्तर की कोल्ड चेन, दुग्ध परीक्षण सुविधाओं, और गुणवत्ता तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन पर प्रशिक्षण का भी समर्थन करता है।

घटक ख: सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी

किसानों की संगठित बाजारों तक पहुंच को बेहतर बनाकर दुग्ध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने का प्रयास करता है। यह डेयरी प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना का समर्थन करता है और किसानों के आय में सुधार के लिए उत्पादक-स्वामित्व वाली संस्थाओं को सुदृढ़ करता है।

घटक ख नौ राज्यों में लागू किया गया है: आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

31 अक्टूबर, 2026 तक एनडीडीडी की भौतिक उपलब्धियां

- **40,800 नई डेयरी सहकारी समितियां** संगठित/पुनर्जीवित की गईं।
- **25.82 लाख** अतिरिक्त किसान नामांकित हुए और **161.17 लाख** अतिरिक्त दुग्ध खरीद की गई।
- **168 लाख लीटर प्रति दिन** दुग्ध ठंडा करने की क्षमता बनाई गई।
- **94,000 दुग्ध** गुणवत्ता परीक्षण उपकरण वितरित किए गए।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था, जो विशेष रूप से स्वदेशी गोवंशीय नस्लों

के वैज्ञानिक समग्र विकास और संरक्षण के लिए है। यह योजना दुग्ध उत्पादन और गायों की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ताकि दुग्ध की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बनाया जा सके। मार्च 2025 में संशोधित, यह योजना प्रजनन अवसंरचना को सुदृढ़ करने और उन्नत प्रजनन तकनीकों तक पहुंच बढ़ाने पर जोर देती है। इसके हस्तक्षेपों में वीर्य स्टेशनों को मजबूत करना, कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का विस्तार करना, और लिंग-सॉर्टेड वीर्य और आईवीएफ तकनीक जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से नस्ल सुधार को तेज करना शामिल है।

आरजीएम के अंतर्गत प्रगति,

- **ग्रामीण भारत में 50,023** बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन प्रशिक्षित और सुसज्जित।
- **24** इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) प्रयोगशालाएं स्थापित।
- **48** वीर्य स्टेशनों को मजबूत किया जा रहा है।
- **32** हेफर पालन केंद्र स्वीकृत।

<u>देशव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनएआईपी)</u>

यह कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना और उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले बैलों सहित स्वदेशी नस्लों के वीर्य के साथ किसानों के दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करना चाहता है।

- **18.71** करोड़ से अधिक कृत्रिम गर्भाधान किए गए।
- लगभग **11.17 करोड़** जानवरों को कवर किया गया।

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) निजी क्षेत्र और सहकारी समितियों में आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और कोल्ड-चेन अवसंरचना का समर्थन करता है।

- यह पात्र लाभार्थियों को 8 वर्षों के लिए **3 प्रतिशत ब्याज अनुदान** प्रदान करता है।
- पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के माध्यम से **258 डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों** को निजी क्षेत्र और सहकारी समितियों के लिए वर्ष 2020-21 से 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ समर्थन मिला है। इससे लगभग **21,797 करोड़** रुपये का निवेश हुआ है।
- **500.58 लाख लीटर प्रति दिन** दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता और मूल्यवर्धन क्षमता के साथ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुधन रोगों की रोकथाम और नियंत्रण का समर्थन करता है। यह पशु चिकित्सा अवसंरचना को भी मजबूत करता है और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के माध्यम से घर-घर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है।

31 अक्टूबर 2026 तक,

- **4,019 एमवीयू** 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत थे।
- इन इकाइयों ने लगभग **1.5 करोड़ किसानों** को घर-घर सेवाएं प्रदान की हैं और लगभग **3.3 करोड़ पशुओं** का उपचार किया है।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जो एमएचडीसीपी का एक घटक है, फुट एंड माउथ डिजीज (एफएमडी) नियंत्रण और अंततः उन्मूलन का समर्थन करता है, साथ ही टीकाकरण और निगरानी के माध्यम से ब्रुसेलोसिस नियंत्रण भी करता है।

31 अक्टूबर 2026 तक,

- कुल एफएमडी टीकाकरण 152 करोड़ से अधिक खुराकों तक पहुंच गया, जिससे लगभग 8 करोड़ किसानों को लाभ हुआ।
- एफएमडी प्रकोप 2019 में 132 से घटकर 2025 में 40 रह गए।
- ब्रुसेलोसिस के प्रकोप 2019 में 22 से घटकर 2025 में 15 हो गए।

भारत पशुधन के माध्यम से डिजिटल पशुधन रिकॉर्ड

पशुपालन और डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से ***"भारत पशुधन"*** डेटाबेस विकसित किया है। भारत पशुधन डेटाबेस में पंजीकृत जानवरों की पहचान एक अनूठे 12-अंकीय ईयर-टैग नंबर के माध्यम से की जाती है, जिसे ***"पशु आधार"*** *के नाम से जाना जाता है।* यह जानवरों पर किए गए सभी प्रकार के लेन-देन जैसे टीकाकरण, प्रजनन, उपचार आदि को पंजीकृत करने के लिए एक प्राथमिक कुंजी के रूप में कार्य करता है। यह डेटाबेस पहचाने गए जानवरों का डिजिटल रिकॉर्ड प्रदान करता है और पशुधन प्रबंधन का समर्थन करता है।

31 अक्टूबर 2026 तक,

- **9,98,55,955** पशुधन मालिकों का पंजीकरण किया गया है।
- **39.42 करोड़** से अधिक पशु आधार जारी किए गए हैं।

वैश्विक बाजारों में भारतीय डेयरी उत्पाद

भारत का डेयरी क्षेत्र एक बड़े घरेलू बाजार की सेवा करता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है।

- भारत ने वर्ष **2025-26** के दौरान 97,524.82 मीट्रिक टन डेयरी उत्पादों का निर्यात किया।
- वर्ष के दौरान निर्यात आय 407.12 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई।

- प्रमुख निर्यात गंतव्यों में **यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, भूटान** और बहरीन शामिल थे।

ये निर्यात भारत के डेयरी उत्पादों की पहुंच को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दर्शाते हैं, जिससे इस क्षेत्र की उपस्थिति घरेलू खपत से परे भी बढ़ती है।

हर बूंद के पीछे की ताकत

भारत की डेयरी यात्रा लाखों किसानों, महिलाओं और सहकारी संस्थानों के योगदान को दर्शाती है। बढ़ता हुआ दुग्ध उत्पादन, मजबूत अवसंरचना, वैज्ञानिक प्रजनन और बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवा इस क्षेत्र के विकास का समर्थन करती रहती है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस डॉ. वर्गीस कुरियन की विरासत का सम्मान करता है और उन किसानों को मान्यता देता है जिनके प्रयास भारत के डेयरी नेतृत्व को बनाए रखते हैं, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करते हैं और राष्ट्र की पोषण सुरक्षा में योगदान देते हैं।

संदर्भ

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

https://www.dahd.gov.in/static/uploads/2026/06/9ae804b82e59e283443396dbb5a245e0.pdf
https://www.dahd.gov.in/static/uploads/2026/04/29232c53442fadce97015a62fd715e74.pdf
https://www.nddbdairyservices.com/milkproducer
https://www.nddbdairyservices.com/aboutUs
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2241603&reg=3&lang=1
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2287675&reg=48&lang=2
https://www.dahd.gov.in/offerings?page=1
https://www.dahd.gov.in/offerings/schemes-and-services/details/national-programme-for-dairy-development-npdd-EjN5UTMtQWa
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2298197&reg=48&lang=2
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2110279&reg=3&lang=2
https://www.dahd.gov.in/offerings/schemes-and-services/details/livestock-health-disease-control-program-lhdcp-MzN5UTMtQWa
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204580
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2298199
https://bharatpashudhan.ndlm.co.in/

सहकारिता मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2238399&reg=3&lang=1
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2247837
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2291129
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2247837&reg=48&lang=2
https://sansad.in/getFile/annex/268/AU3046_BTEYKH.pdf?source=pqars
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2294896

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

https://apeda.gov.in/DairyProducts

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2317937&lang=1&reg=3

पीआईबी बैकग्राउंडर

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2194086&reg=3&lang=2
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2302242
https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?id=150838&ModuleId=16&reg=percent203&lang=1
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2212724&reg=3&lang=2
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2026/aug/doc202686946301.pdf

पीआईबी शोध

पीके/केसी/आरटी/एचएन/एम